

प्रेषक,

डा० पी०एस० गुसाई,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियां,  
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 19 अप्रैल, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु लेखानुदानावधि में विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या- 67/नियो०/सह०परिषद/2012-13 दिनांक 4 अप्रैल, 2012, वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या:-193/XXVII (1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में लेखानुदानावधि में दि० 1 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक चार माह के लिए सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु कुल धनराशि ₹ 6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह में 5 तारीख तक बी०एम०-5 प्रपत्रपर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा बी०एम० 13 प्रपत्र पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।
6. वचनबद्ध तथा अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

कमशः

(2)

2-उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-18 के 2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय-20-सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन -00-की मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3:- ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या:-193/XXVII (1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० पी०एस० गुसाईं)  
सचिव।

संख्या:- 6\3(1)/XIV-1/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- ✓ 9. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,  
(देवेन्द्र पालीवाल)  
उपसचिव।